

संपादकीय



सोशल मीडिया की स्पीड

जून 2020 में टिकटों का बिकना होने के बाद शॉर्ट वीडियो की दुनिया लंबा रास्ता तय कर चुकी है। इंटरस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक तो हैं ही, एमएक्स, मीमा, जोश, चिंगारी, मित्रों जैसे ऐप भी इस दुनिया में तहलका मचाए हुए हैं। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर जिस तरह से फेक न्यूज और आरोप-प्रत्यारोपों की बाढ़ आ गई थी, इसके यूजर विकल्प की तलाश में थे। इसी विकल्प की भरपाई रील्स कर रही हैं। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे जल्दी से बढ़ता इंटरनेट यूजर बेस को होस्ट करने वाला देश है। यहां फिल्में, उनके डायलॉग और म्यूजिक हमारे जीवन में इस हद तक घुसे हुए हैं कि उनके बगैर जीवन की कल्पना करना मुश्किल है। हर कोई कैमरे के सामने सिलिब्रिटी बनना चाहता है, जिसकी दुनिया बढ़ती जा रही है। 2016 में रिलायंस जिओ के लॉन्च के बाद सस्ते डेटा ने रील्स को भारत में पांच पसारने का बेहतरीन मौका दिया। रेड्डीशी कंसल्टिंग फर्म की एंटरटेनमेंट एंड एक्सप्लोरेंसिंग वॉशिंगटन डीजलिवल वेव रिपोर्ट के अनुसार फेसबुक और गूगल के बाद दूसरा सबसे बड़ा सेगमेंट रील्स ही है, जहां लोग सबसे ज्यादा समय बिता रहे हैं। शॉर्ट वीडियो बनाने की सुविधा देने वाली वेबसाइट या ऐप के यूजर्स की संख्या साल 2025 तक 65 करोड़ हो जाएगी। इसी रिपोर्ट के अनुसार शॉर्ट वीडियो आने वाले वर्षों में ओटीटी वीडियो इंस्टेंट को भी पछाड़ देगा। डिजिटल विज्ञानों की दुनिया में वीडियो के ये लघु संस्करण तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं। साल 2019 से 2022 के बीच यह सेगमेंट 44 प्रतिशत की रफ़्तार से बढ़ा। इसकी वजह टियर टू शहरों में इंटरनेट का फैलाव है, जिसने एक नयी माफ़ेत पैदा की है, जहां ब्रंड उम्पठाता तक सीधे पहुंच बना रहे हैं। यह फालो आने वाले वर्षों में बहुत तेजी से बदलेगा। इन रील्स को बनाने में किसी प्रॉडक्शन हाउस की मदद नहीं ली जा रही है। इसकी बड़ी वजह है रील बनाने के प्लेटफॉर्म में आसान इंटरफ़ेस। इसमें किसी को तकनीकी का महारथी होना भी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ सवाल ऐसे भी हैं जिनके जवाब अभी खोजे जाते हैं। पहला मुद्दा तो निजता का ही है। टियर टू शहरों से आने वाली रील्स ज्यादातर लोगों के निजी परिवेश को ही दिखा रही हैं। दूसरा मुद्दा है अभीलता का। तीसरा, दूसरों के कंटेंट को एडिट कर अपना बना लेने की भी कलायद बढ़ा खूब हो रही है। चौथा, लोगों को बिना अनुमति के उनकी वीडियो रील्स में डाली जा रही हैं। इंटरनेट के फैलाव ने बहुत सी निहायत निजी चीजों को सार्वजनिक कर दिया है। ऐसे में हम उन असामान्य घटनाओं को भी सार्वजनिक जीवन का हिस्सा मान लेते हैं, जिसने एक परंपराइक समाज का जन्म होता है। शायद यही वजह है कि अब दुर्घटना होने पर लोग मदद की बजाय वीडियो बनाने में लग जाते हैं कि उससे बचावदी हो जाए। और अंत में सबसे बड़ा मुद्दा रील रेटर्न में समय की बर्बाद का है, जिसमें दर्शक कोल्लू के बेल की तरह चलता तो बहुत है पर पहुंचना कहीं नहीं। तो पहले यह तय हो कि हम क्या और क्यों कर रहे हैं।

सामयिकी

बिलावल व राहुल संभल कर बोले

डॉ. वेदप्रताप वैदिक

पाकिस्तान के विदेश-मंत्री बिलावल भुट्टो और काग्रिस के मालिक राहुल गांधी के बयानों पर भारत में तीखी प्रतिक्रिया रही है। पता नहीं, इन दोनों पाटियों-मालिकों के बयानों पर भाजपा-कारकों को इतना नाराज होने की जरूरत क्या है? गांधीज तर्क बिलावल का सवाल है, वह जब छोट्टा बच्चा था तो अपनी मां-बेन-जोरी के साथ मुझसे मिलने अस्सर दुर्दई में आया करता था। अब वह हम-अचानक पार्टी का मुखिया और विदेश मंत्री बन गया है। उसके मुंह से यह-वह अविगम्य बयान नहीं निकलता जो पाकिस्तान में उस कौन गांठिग-वहव अवसे नाना जुल्फकार अली भुट्टो से भी आगे निकलना चाहता है। इसीलिए उसने अपना उनामान अपने पिता जख्दार की रखने की बजाय अपने-नाना भुट्टो का रख लिया है। भुट्टो कहा करते थे कि भारत से यदि हजार साल भी लड़ना-पड़ने तो वे लड़ते रहेंगे, लेकिन वे कश्मीर लेकर रहेंगे। बेनजोरी से भी जब-जब भी मिला तो मैं उससे कहा कि आप कश्मीर लेने के चक्कर में मैं पाकिस्तान खो बैटंगी। फौज के तले दबे हुए पठान, बलूच और सिंधी-आपके देश के कई टुकड़े कर देंगे। मुझे न्यायस था कि बिलावल बोदी-होकर इस मुष्ट पर ध्यान देना, लेकिन उनसे न्यूयार्क में प्रधानमंत्री नेरन्द मोदी की तुलना कुख्यात आतंकवादी आसामा बिन लादेन से कर दी। अब जबकि-प्रधानमंत्री शहाबज शरीफ और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान काफी संतुलित-बयान दे रहे हैं, बिलावल ने ऐसा अतिवादी बयान देकर अपनी छवि बनाई-लिया बिगाड़ी है, वह जरा खुद सोचें। इसी तरह राहुल गांधी ने तवांग में हड़त-छुटपुट भारत-चीन मुठभेड़ के बारे में कुछ ऐसी बातें कही हैं कि जो-उल्टे बास बोली जैसी लगती हैं। उन्होंने पूछा है कि गलवान घाटी कांड-के और उसके पहले चीन ने जो हमारी जमीन छीनी है, उसके बारे में मोदी-चुप क्यों हैं? राहुल को शायद पता नहीं कि उसके परनाना नेहरूजी के-जमाना में हमारी लगभग 38 हजार किलोमीटर जमीन पर चीन ने कब्जा-कर लिया था और 1962 के युद्ध में भारत को भारी शर्मिंदगी उठानी पड़ी-थी। छिल्ले पांच-छह दशक के शासनकाल में वह काग्रिस ने उस जमीन-की वापसी के लिए कभी कोई ठोस कोशिश की? राहुल के पिता और पूर्व-प्रधानमंत्री राजीव गांधी तो चीन के नेताओं से गलत-मिलविल के लिए-1988 में बीजिंग भी पहुंच गए थे। काग्रिस ने मोदी से तवांग पर सात सवाल-पूछे हैं, उनमें से कुछ तो बिल्कुल सही हैं, जो विरोधी दलों को उठाना ही-चाहिए लेकिन ये सवाल जिन-वह से पूछे गए हैं, वे भारत के राहद्वितों-का अहंता तो करते ही हैं और बहुरंग फौजियां का मोनेबल भी गिराते हैं-तो काग्रिस की राजीव गांधी फाउंडेशन का चीन से जो लेन-देन रहा है, वह भी-उन बयानों से बराबर उजागर होता है। इसीलिए बिलावल भुट्टो और राहुल-गांधी, जैसे युवा नेताओं को इस तरह के विवाददास बयान देते समय कुछ-अपभ्रवी सलाहकारों से परामर्श जरूर कर लेना चाहिए।

(लेखक, भारतीय विदेश नीति परिषद परिषद के अध्यक्ष हैं।)



योगेश कुमार गोयल

रैगिंग के खिलाफ बनाए गए एंटी रैगिंग कॉल सेंटर में दर्ज कराए गए मामलों पर नजर डालें तो 2019 तक 11 वर्षों में कॉल सेंटरों में कुल 6187 केस दर्ज हुए। इनमें सर्वाधिक 1078 केस वर्ष 2018 में दर्ज हुए।



अरिजीत बर्मन

यह दलील दी जा सकती है कि इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हालिया गाइडलाइंस में कंटेंट पब्लिशर्स के लिए डिजिटल कोड है। अगर ऐसी बात है, तो एजुटेक यूनिर्कॉन को उसके दायरे में लाया जाना चाहिए। निशीथ देसाई एसोसिएट्स की अटॉर्नी आरुषि जैन कहती हैं, कंज्यूमर फोरम भी पीड़ित अभिभावकों और छात्रों की मदद कर सकते हैं। हालांकि, ये सभी कानून नए हैं।



डा. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

रवांडा
ऐसा देश है जहाँ
संसद में
महिलाओं की
हिस्सेदारी 61
फीसदी से भी
अधिक है। इसी
श्रेणी में 53
फीसदी के साथ
व्यूबा, 50
फीसदी के साथ
निकारागुआ,
मेक्सिको और
यूएई आते हैं तो
47 प्रतिशत से
अधिक की
हिस्सेदारी के
साथ आइसलैंड
आ जाता है।

भारत में तकनीक के माध्यम से शिक्षा देने वाली यानी एजुकटेक कंपनियों का कारोबार तेजी से फलफूल रहा है। इस साल अकेले अगस्त में ही ऐसी तीन कंपनियाँ यूनिकॉर्न क्लब में शामिल हुईं। यूनिकॉर्न यानी एक अरब डॉलर से ज्यादा वैल्यू वाली कंपनी। अब यूनिकॉर्न क्लब में भारत की कुल 5 एजुकटेक कंपनियाँ हैं। चीन में तो इन कंपनियों का साइज और भी बड़ा है। तो क्या वहाँ के स्कूली बच्चों का हाल भी हमारे बच्चों जैसा है? चैनेन में स्कूल जाने वाले बच्चे के पैरेंट्स और अंतर के चेंगदू में रहने वाले पैरेंट्स में कोई अंतर है?

माँ-बाप दोनों ही जगहों पर परेशान हैं। दोनों ही जगहों पर लोग अपने बच्चों के लिए अच्छी से अच्छी डिग्रियाँ चाहते हैं और उसके लिए अपनी सारी जमा-पूँजी दाँव पर लगाने को तैयार हैं। स्कूली पढ़ाई खत्म होने के बाद पैरंट्स बच्चों को कॉलेज से लेविएस तक सारी सहायताएँ देने की कोशिश करते हैं, ताकि वे प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। चीन में नेशनल कॉलेज एंट्रेंस एग्जामिनेशन गाओआओ है, तो भारत में जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम यानी जेएच है। एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनियाँ तो हमारे यहाँ शुरूआती दौर में हैं। चीन में यह सब काफी पहले शुरू हो चुका है। वहाँ हई एक स्टडी बताते हैं कि बड़े शहरों में पढ़ाई पर कुल खर्च का करीब 44 फीसदी हिस्सा ट्यूशन में जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा लगभग 16 फीसदी है। चीन में 2017 से 2019 के बीच प्राइवेट ट्यूशन में 30 फीसदी बढ़ोतरी देखी गई। इधर, भारत में भी हर तीन में एक स्कूली बच्चा कॉलेजिंग या ट्यूशन ले रहा है। कॉविड महामारी के दौर में तो ऑनलाइन कॉलेजिंग को पंख लग गया। कोई भी एजुकटेड कंपनी इसका फायदा उठाने में पीछे नहीं रहती। चाहे वह भारत की बायजूज और अनएकेडमी या फिर चीन की न्यू ओरिएंटल एजुकेशन और कुलन ऑनलाइन कॉलेजिंग इंस्टिट्यूट की बाढ़ ने चीन को सख्त कमजोर उठाने पर मजबूर कर दिया। उसने दमजल इंटरनेट कंपनियों की नकेल कसी। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या भारत को भी एजुकटेड कंपनियों के लिए नियम कानून बनाने चाहिए?

दरअसल चीन की तरह भारत में भी



आर्नालाइन एजुकेशन की सुविधाओं ने एक बड़ी खाई बना दी है। यहाँ तो पहले से पढ़ाई-लिखाई की एक जैसी सुविधा सबको नहीं मिल पा रही थी, अब डिजिटल दौर में यह अंतर और बढ़ रहा है। किसी बच्चे के पास लैपटॉप, टैबलेट, इंटरनेट सब कुछ है, दूसरे के पास कुछ भी नहीं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि चीन की सख्ती ने इंडियन टेक इंडस्ट्री के लिए अपार संभावनाओं का दरवाजा खोल दिया है। एजुकटेक फर्मों ने दो साल में कोचिंग से करीब 4 अरब डॉलर की कमाई की है। इसमें 50 फीसदी कॉर्पा के पिछले 6 महीने में ही हुई। बायजूज अब दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली एजुकटेक स्टार्टअप है।

इन सबसेके बावजूद एजुकटेक इंडस्ट्री के लिए कायदे-कानून का एक ढांचा बनाना जरूरी है। चीन जितनी सख्ती तो नहीं होनी चाहिए। लेकिन सरकार को संतुलन बनाने के लिए कुछ करना होगा, क्योंकि पैरंट्स की शिकायतों में बेतहाशा इजाफा हुआ है। इन कंपनियों के जाल में फंसने के बाद पैरंट्स पर पर्ज का बोझ बढ़ता ही जाता है। केवल मुनाफे के लिए काम करने वाली कंपनियों एजुकटेक कंपनियों तो कोचिंग इंस्टिट्यूट बन गईं हैं। ये कंपनियां कोचिंग इंस्टिट्यूट और मुनाफाखोरी करने वाले स्कूलों का विकल्प बनने आई थीं, लेकिन मुनाफा कमाने की

होड़ में उन्हीं की तरह बनती जा रही हैं। एक बेसिक दिक्कत एजुटेक के स्ट्रक्चर से जुड़ी है। पढ़ाई-लिखाई हर बच्चा अपनी स्पीड से करता है। सबकी समझ का अपना एक लेवल होता है और उसी हिसाब से सीखने से जुड़ी चुनौतियाँ होती हैं। लेकिन इन कंपनियों का पैकेज तो मोटे तौर पर फिट फॉर ऑल सीरखा है। उसमें हर बच्चे पर अलग से ध्यान दे पाना संभव नहीं।

एक पहलू फीस का भी है। करीब 20-30 साल पहले जो कोचिंग क्लासेज चलती थीं, उसमें लॉन्ग टर्म पेमेंट जैसे कोई बैंक नहीं होती थी। अमूमन एक महीने की फीस ली जाती थी, वह भी महीना खत्म होने के बाद आपको पर्सद आए तो पहिए नहीं तो दूसरी कोचिंग में चले जाएँ। लेकिन अब मल्टी-इयर पैकेज जैसे ऑफर थोपे जा रहे हैं। कहीं पैरेंट्स को थर्ड-पार्टी लेन्डर्स से पढ़ाई के लिए कर्न लेना पड़ जाता है। उसकी मुसीबत अलग ही है। अगर आप सोशल मीडिया पर किसी एजुटेक कंपनी की आलोचना करते हैं, तो आप पर मुकदमा भी लाद दिया जाएगा। यह इस इंडस्ट्री की एक और बड़ी खराबी है।

सरकार के पास डिजिटल एजुकेशन बढ़ाने की क्षमता नहीं है। उसके पास साधन भी सीमित हैं। सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर आने वाले वक्त में शायद ही बेहतर हो पाए। लिहाजा,

इस क्षेत्र में ग्राहवेत कंपनियों का एकाधिकार रहेगा। उनका उद्देश्य कर्बों से लेकर दूर-दराज के गांवों तक फैल जाएगा। वेंचर कैपिटलिस्ट जिस तरह से एजुकटेड इंस्टीट्यूट पर दांव लगा रहे हैं, उससे यह समस्या और बढ़ रही है। पहले बड़े उद्योगपति अपनी कमाई का कुछ हिस्सा जनता की भलाई वाले कामों में लगाते थे। लेकिन, अब उनका मकसद देश के तेजी से बढ़ते इंटरनेट मार्केट में निवेश कर मुनाफा कमाना भर रह गया है। परिवर्परक शिक्षा व्यवस्था हमेशा से सख्त निगरानी के दायरे में रही है। अब महामारी के चलते पढ़ाई-लिखाई का सारा सिस्टम ऑनलाइन हो गया है। ऐसे में यह देखना अजीब लगता है कि अरबों डॉलर वाली एजुकटेड कंपनियों पर सरकार की ओर से कोई बंदिश नहीं है।

येक हलदी दी जा सकतो है कि इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की हालिया गाइडलाइन्स में अंतर प्रविष्टिबाधक के लिए डिजिटल कोड है। अगर ऐसी बात है, तो एज्युकेट यूनिवर्स को उसके दायरे में लाया जाना चाहिए। निश्चित देसाई एसोसिएट्स की अर्दनी आरुषि जैन कहती है, कंजुपर फोरम भी पीडित अभिभावकों और छात्रों की मदद कर सकते हैं। हालांकि, ये सभी कानून न हैं। इन्हें और स्पष्ट करने की जरूरत है ताकि इनकी मदद से परेंट्स और स्टूडेंट्स का शोषण रोका जा सके।

आधी आबादी के लिए न्यूजीलैंड से सुखद संदेश

दुनिया में आधी दुनिया को सबसे पहले मताधिकार देने वाले देश न्यूजीलैंड से यह सुखद संदेश भी आ गया है कि वहां की संसद में महिलाओं की संख्या अब पुरुषों से अधिक हो गई है। न्यूजीलैंड की संसद में 59 पुरुषों के मुकाबले अब 60 महिला संसद हो गई हैं।

उदारवादी लेबर पार्टी की नेता सोरारा पेके मैथसन ने पिछले दिनों संसद के रूप में शायद ही है। न्यूजीलैंड ने 1893 में ही महिलाओं को मताधिकार देकर दुनिया के देशों के सामने एक मिसाल कायम कर दी थी। हालांकि यह भी विचारणीय हो सकता है कि करीब 130 सालों से भी अधिक समय के बाद संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी आधी हुई है पर इसे सकारात्मक सोच के साथ देखा जाना चाहिए। देखा जाए तो दुनिया के करीब आधा दर्जन देश ऐसे हैं जहां की संसद में महिलाओं का प्रतिनिधित्व अच्छा खासा है। खासतौर से रवांडा ऐसा देश है जहां संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 61 फीसदी से भी अधिक है। इसी श्रेणी में 53 फीसदी के साथ ब्रूना, 50 फीसदी के साथ निकारागुआ, मैक्सिको और यूएई आते हैं तो 47 प्रतिशत से अधिक की हिस्सेदारी के साथ आइसलैंड आ जाता है।

हमारे देश में करीब 14 फीसदी ही महिलाओं की भागीदारी है। मजे की बात यह है कि हिमाचल प्रदेश में महिला वोटर अधिक होने के बावजूद केवल और केवल एक महिला चुनाव जीत कर आई है। खैर यह विषयगत होगा। यह मोटे अनुमान के अनुसार अमेरिका में पुरुषों



है-कड़ करीब 27 प्रतिशत के आसपास बढ़ता है तो दुनिया के देशों की अधिकतर संसद में महिलाओं की हिस्सेदारी 22 प्रतिशत से कुछ ही अधिक देखने को मिल रही है। दुनिया के देशों की विधायिका में महिलाओं की हिस्सेदारी को देखते हुए हालाँकि तेजी से बढ़ता आ रहा है पर लोकतंत्र की हामी भरने वाले देशों की तुलना में दुनिया के छोटे और विकासशील देश अधिक आगे हैं। रवांडा देश का यूकूबा या इसी श्रेणी के अन्य देश, यह साफ हो जाता है कि लाख संकटों के बावजूद सत्ता में भागीदारी में महिलाएँ पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। हालाँकि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जैसिडा अर्नर का हालिया बयान महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि कई देशों में महिलाओं की स्थिति को लेकर अनिश्चितता है। हिम जै-जै से आगे बढ़ रहे तो ऐसे लगता है कि हम महिलाओं को प्रगति के मामले में

तेजी से पीछे की ओर खिसकता हुआ देख रहे हैं। हालाँकि वह उनकी अपनी सोच है पर इसमें कोई दोराय नहीं कि सता में भागीदारी को अलग कर दिया जाए तो आज महिलाएँ लगभग सभी क्षेत्रों में सफलता के परचम पहरा रही हैं। कहीं कहीं बात भी है। दुनिया की बड़ी-बड़ी कंपनियों में महिलाओं की अच्छी पकड़ देखी जा रही है तो जल, शल और नभ सभी में महिलाओं ने बिना किसी लैंगिक भेदभाव के अपनी जगह बनाई है। प्रशासनिक स्तरों पर भी महिलाओं की दक्षता का लोहा मना जाने लगा है।

सवा जह है कि दुनिया के विकसित देश और खासतौर से लोकतंत्र की दुहाई देने वाले देश भी आधी दुनिया की भागीदारी में क्यों पिछड़ रहे हैं। आखिर महिला सशक्तिकरण का नारा तो समूची दुनिया दे रही है। कुछ पुरातनपरियों को छोड़ भी दिया जाए तो इसमें अब कोई दोराय

नहीं रही है कि महिलाओं को अब घर और बाहर सभी जगह बराबर का दर्जा दिया जाने लगा है। हालाँकि सामाजिक ताने-बाने में कुछ बदलाव देखने को मिल रहा है। संक्रमण का दौर होने से कुछ विद्वत्ताएं भी सामने आती हैं पर यह तो मानना ही पड़ेगा कि दुनिया के कुछ अतिवादी सोच के देशों को छोड़कर बाकी सब देशों में महिलाओं की भागीदारी लाभप्रद सभी क्षेत्रों में बढ़ी है और लगातार बढ़ रही है।

जहाँ तक हमारा देश का सवाल है एक मोटे अनुमान के अनुसार हमारे यहाँ करीब 14 प्रतिशत हिस्सेदारी है। हालाँकि स्थानीय निकायों में महिलाओं आरक्षण से स्थानीय सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी बढ़ने के साथ ही काफी बदलाव भी देखने को मिला है। पार्षद पति, संपर्क पति, प्रथा पति, प्रमुख पति आदि की देखलंदाजी अब तुलनात्मक रूप से देखें तो काफी कम हुई है। महिलाएं सफलता के साथ अपनी जिम्मेदारी निभाने लगी हैं। ऐसे में यह कहना कि महिलाएं शासन का संघालन नहीं कर सकती पूरी तरह से नकार दिया गया है। देखा जाए तो पुरुषों मिथक टूट रहे हैं। खैर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे अतिविकसित देशों और रूस और चीन जैसे वामपंथी देशों को अब महिलाओं की विधायिका में भागीदारी बढ़ाने के लिए बहुत कुछ करना होगा। हमारे यहाँ चाहे निचले स्तर पर ही हुआ हो पर उसका प्रभाव अच्छे लगा है और आने वाले समय में और अधिक मुखरता देखने को मिलेगी।

(लेखक, स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं।)

रैगिंग का रोग, क्यों खामोश हैं लोग



कलिंग में एक छत्रा के साथ अश्वील रैगिंग में शामिल 12 छात्रों को संस्थान से निष्कासन किया गया। जा चुका है। हैदराबाद के एक बिजनेस स्कूल के आठ छात्रों को कथित रूप से रैगिंग करने और एक छात्र की पिटाई के मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। यही नहीं बिजनेस स्कूल प्रबंधन के नौ सदस्यों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। उत्तराखंड का वीर चंद्र सिंह राजकीय मेडिकल कॉलेज श्रीनगर भी पीछे नहीं है। यहां सीबीएस प्रत्येक वर्ष के छात्रों की रैगिंग करने पर सात सीनियर

छात्रों को तो माह के लिए निर्वासित किया गया और सभी को आर्थीय रूप से होस्टल से निष्कासित किया गया। आईआईटी खड़गपुर के छात्रवास में एक छात्र की रहस्यमय मौत के बाद एंटी रैगिंग संस्वायस बनाने की घोषणा की गई। ड्वोर के डेईक्स मेडिकल कॉलेज में एम्बोबीएस प्रथम वर्ष के छात्र ने तो रैगिंग से परेशान होकर जान ही दे दी। रैगिंग की घटनाओं की फेहरिस्त लंबी हो गई। 2009 में हिमाचल प्रदेश के हंडीकाल कॉलेज में अमन कारकुरी रैगिंग से हई मौत के

बाद सुप्रिम कोर्ट ने कड़े कानून का प्रावधान किया था। साथ ही देश के प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में रैगिंग के खिलाफ एफ़ सर्मिती बनाने का आदेश दिया था। जस्टिस अरिजिता पसायत, जस्टिस डी. के. जैन तथा जस्टिस मुकुन्दम शर्मा की के. जे. खंडपीठ ने 11 फरवरी, 2009 को कहा था कि रैगिंग में मानवाधिकार हनन जैसी गंध आती है। रैगिंग पर सख्त और कड़े शासित प्रदेश शिक्षण संस्थानों में पर रोक लगाने के लिए राघवन कामेटेई की सिफारिशों को खूबी से लागू करें।

रैगिंग रोकने में विफल रहने वाले शिक्षण संस्थाओं की मान्यता रद्द की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने 2001 भी उन्नीकृष्णन समिति की सिफारिश के आधार पर रैगिंग पर प्रतिबंध लगाते हुए इसके लिए कठोर सजा का प्रावधान करते हुए अपने आदेश में स्पष्ट कहा था कि शिक्षा प्रसारा में रैगिंग रोकना शिक्षा संस्थानों का नैतिक ही नहीं, कानूनी दायित्व भी है।

चिंता की बात है कि सख्त अदालती निर्देशों के बावजूद रैगिंग नासूर बनकर नवोदित छात्रों को भविष्य बर्बाद कर रही है। कोविड काल से पहले के आंकड़े देखें तो रैगिंग के खिलाफ सख्त कानून बनने के बावजूद 18 अप्रैल 2012 से लेकर 23 अगस्त 2019 तक करीब सात वर्षों की अवधि में रैगिंग की 4893 शिकायतें सामने आईं जबकि इन सात वर्षों में 54 छात्रों ने रैगिंग से परेशान होकर अपना जीवन खत्म करके की राह चुनी। रैगिंग के खिलाफ बनाए गए एंटी रैगिंग काल सेंटर में दर्ज कराए गए मामलों पर नजर डालें तो 2019 तक 11 वर्षों में कॉल सेंटरों में कुल 6187 रैगिंग केस दर्ज हुए। इनमें सर्वाधिक 1078 रैगिंग केस वर्ष 2018 में दर्ज हुए। वर्ष 2017 में किए गए एक सर्वे के अनुसार तो देश के अधिकांश कॉलेजों में करीब 40 फीसदी छात्रों को किसी न किसी रूप में रैगिंग या सीनियर छात्रों द्वारा धमकाने का सामना करना पड़ा। गहराहाल, यह जरूरत इस बात की है कि कॉलेज प्रशासन रैगिंग में लिप्त पाए जाने वाले छात्रों के खिलाफ ऐसे कठोर कदम उठाए, जो न केवल उस कॉलेज बल्कि अन्य कॉलेजों के छात्रों के लिए नजीर बनें।

धनंजय त्रिपाठी ने किया कोस्को क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन

मेदिनीनगर पलामू/जी॰एल॰ए कॉलेज परिसर में शहीद ए आज़म भगत सिंह नॉक आउट कोस्को क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह का उद्घाटन किया व विजेता टीम को ट्रॉफी देकर उज्ज्वल भविष्य का शुभकामनाएं दिया।

मुखिया 11 व पियांकी फाइटर के बीच फाइनल मैच खेला गया जिसमें पियांकी फाइटर विजयी हुई

अब तक एक मिलियन से अधिक गरीबों को राहत पहुंचा चुके है

समाजसेवी शौकत खान

मेदिनीनगर पलामू/जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे कपड़ा बैंक गढ़वा में जरूरतमंदों को उमड़ रही है प्रतिदिन नारी भीड़ अभी गढ़वा की ताम्रामन आठ नौ डिग्री सेल्सियस तक आ चुका है ऐसे में उन गरीब परिवार के लिए मुश्किल हो रहा है जिनके पास ठंड से बचने कि बेवस्था नहीं है ऐसे वक्त में गरीबों के लिए शौकत खान का का कपड़ा बैंक गरीब असहाय लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा है तभी तो लोग गढ़वा जिले के अन्य जगहों से लोग कपड़ा बैंक में भाड़ा किराया लगाकर इस उम्मीद से आते हैं कि शौकत खान के पास से कोई खाली हाथ कभी भी नहीं लौटता और इन सभी जरूरतमंदों के भरोसा पर सौ फीसदी खरे उतरे हैं शौकत खान तभी तो अब तक एक मिलियन से अधिक जरूरतमंदों को राहत पहुंचा चुके हैं अनेक नि:शुल्क बैंक के संस्थापक शौकत खान से पुछने पर बताते हैं कि मैं मैं अपने को बहुत सोभाव्यशाली मानता हूं कि ईश्वर ने मुझे मानवता कि सेवा करने का मौका दिया है जहां सैकड़ों लोग प्रतिदिन खाली हाथ आते हैं और अपनी जरूरत कि चिजे झोले भर परकर ले जाते है और हमारे इस महान सेवा कार्य में आम नागरिकों का बहुत बड़ा योगदान है जिनके सहयोग से हम सेवा दे पा रहे हैं और उस से बड़ी बात ये है कि हमारा अनेक नि:शुल्क बैंक सेना और शहीदों के सम्मान में समर्पित है इसलिए ईश्वर भी साक्षात खड़े होकर रोज सैकड़ों गरीबों को सारी चीजें आसानी से उपलब्ध कराने में मुझे सहयोग करते हैं !

जरूरतमंद बच्चे को स्वेटर देकर उन्हें सम्मानित करते झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता दिपु चौरासिया

मेदिनीनगर पलामू/आज ठंड के बढ़ते प्रकोष्ठ को देखते हुए गरीब और जरूरतमंद बच्चे को स्वेटर देकर उन्हें सम्मानित करते झारखंड मुक्ति मोर्चा के युवा नेता समाजसेवी चेंबर के महानगर अध्यक्ष दीपू चौरसिया दीपू चौरसिया ने कहा जरूरतमंदों की सेवा सबसे बड़ी सेवा होती है इस ठंड को देखते हुए आज बाजार क्षेत्र में गरीब बच्चों के बीच स्वेटर का वितरण किया गया और हम लोग सभी व्यवसाई भाइयों के सहयोग से हमेशा जरूरतमंदों की सेवा की जाती है और हम सभी संस्था वाले से भी अपील करते हैं कि इस ठंड के मौसम में जरूरतमंदों की सेवा हमेशा आप सभी करते आ रहे हैं आप सभी विभिन्न संगठनों के सभी पदाधिकारी गण और सदस्यगण सभी को हमारी तरफ से बहुत शुभकामनाएं साथ में हमारे कमल जैस्वाल जी पंकज शर्मा जी कुंदन गुप्ता जी साथ थ

पलामू जिला दो कराटेकारो ने कराटे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में चुस्ती-फुर्ती के साथ अपनी कला का प्रदर्शन किया अदिनाथ देव

मेदिनीनगर पलामू/पलामू जिला दो कराटेकारो ने कराटे वर्ल्ड कप चैंपियनशिप में चुस्ती-फुर्ती के साथ अपनी कला का प्रदर्शन करते हुए फाईट एंव काता में चार मे मेडल की जीत अपने नाम किया! जिससे झारखंड एंव पलामू जिला नाम एक बार फिर ऊँचा हुआ! जिसका नाम इस प्रकार है- पलामू मिल्साड मार्शल आर्ट्स टाईगर्स एकेडमी के रवि नयन (53 किलोग्राम भार कटेगरी में)फाईट में गोल्ड मेडल और काता में सिल्वर मेडल एंव संत मरियम विद्यालय के ओम प्रकाश (48 किलोग्राम भार कटेगरी में) फाईट में गोल्ड मेडल और काता में सिल्वर मेडल इत्यादि! यह कराटेकार भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे थे! कराटेकारो को मेडल कराटे वर्ल्ड कप कमिटी के अध्यक्ष काँचो बोध नारायण यादव के द्वारा दिया गया! यह कराटे वर्ल्ड कप चैम्पियनशिप वर्ल्ड यूनाइटेड कराटे डूँ फेडरेशन एंव स्पोट्स कराटे एसोसिएशन ऑफ इंडिया के तत्वावधान में 18-19 दिसम्बर-022 को ईस्टर्न रेलवे स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स स्टेडियम में आयोजित किया गया था! यह जानकारी मुख्य कराटे प्रशिक्षक शिहान संतोष कुमार के द्वारा दिया गया

राजहरा कोलियरी में नहीं शुरू हुआ खनन, यथावत बनी हुई है पूर्व की स्थिति: किशोर

अभिभावक संघ के प्रदेश अध्यक्ष व सुप्रीम कोर्ट अधिवक्ता किशोर कुमार पांडेय ने रविवार को राजहरा कोलयरी का निरीक्षण कर स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि देश का सबसे पुराना और एशिया में सर्वोत्तम क्वालिटी के कोयले उत्पादन के लिए मशहूर रहा राजहरा कोलियरी आज अपनी स्थिति पर आठ - आठ आंसू बहा रहा है। हालांकि बन्द पड़े खानदान को पुनः चालू कराने के लिए काफी प्रयास किया गया है वावजूद अभीतक कोई सफलता नहीं मिली है जिसके कारण लोगों में निराशा व्याप्त है। श्री पांडेय ने कहा कि राजहरा कोलियरी पलामू का लाइफलाइन (LifeLine) माना जाता है। इसकी शुरूआत ब्रिटिश शासनकाल 1842 में बंगाल कोल कंपनी ने किया था। आजादी के बाद 1969 में इसका सरकारीकरण हुआ था। यहां के खदानों में एशिया का गुणवत्तापूर्ण कोयला पाया जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक, राजहरा कोलियरी की परिधि में कोयले की अक्रूत भंडार है। इसके सर्वे के बाद जो रिपोर्ट दी गयी है उसमें यह कहा गया है कि यदि निरंतर भी कोयले का उत्खनन किया जाय तो 50 साल तक कोयले की कमी नहीं रहेगी। वहां मौजूदा संसाधन से प्रतिवर्ष 0.75 मिलियन टन उत्पादन किया जा सकता है। वावजूद पिछले 13 वर्षों से उक्त कोयलरी में उत्पादन टप है। इससे जुड़े हजारों लोग आज भी बेरोजगारी की दंश झेल रहे हैं। प्रशासनिक व जनप्रतिनिधियों के रवैया से स्थानीय लोगों में घोर निराशा हैं। राजनीतिक दल के नेताओं के आश्वासन व वायदे से अबतक लोगों की काने पक चुकी है। अबतक इतने वायदे और घोषणा के वावजूद कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आया है। श्री पांडेय ने कहा कि राजहरा कोलियरी में दोबारा उत्पादन शुरू होने से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 15 से 20 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। साथ ही पलामू के आर्थिक विकास में भी यह कोलयरी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकती है। इतना ही नहीं राजहरा कोलियरी पलामू जिले का एकमात्र सरकारी कोलियरी उपक्रम है। उन्होंने उक्त कोयलरी को पुनः चालू कराने की मांग की है ताकि बेरोजगारों को भी रोजगार उपलब्ध हो सके और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सके।

संत तुलसीदास कॉलेज के कर्मियों ने किया एक दिवसीय शैक्षणिक हड़ताल

विश्रामपुर पलामू/रेहला बी मोड़ स्थित संत तुलसीदास इंटर कालेज कर्मियों ने एक दिवसीय शैक्षणिक हड़ताल किया। कॉलेज के शैक्षणिक व गैर शैक्षणिक कर्मियों ने आठ सूत्री मांगों के समर्थन में कॉलेज गेट के समक्ष धरना दिया। सरकार के गलत नीतियों के विरुद्ध मे प्रदर्शन भी किया। कॉलेज के प्राचार्य अरुण कुमार धर दुबे ने बताया कि हमारी प्रमुख मांगों में वित्त रहित स्कूल -कॉलेजों का अधिग्रहण,घाटा- अनुदान, अनुदान की राशि सीधे शिक्षक-कर्मचारियों के खाते में भेजने,सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष करने,महंगाई को देखते हुए उच्च विद्यालय के अनुदान स्लैब में संशोधन करना आदि शामिल है। उन्होंने कहा कि विगत 20- 25 वर्षों से हम सब अपनी मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा सदन में आश्वासन देने के बाद भी आज तक शिक्षक-कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल रहा हैं। कोरोना काल में कॉलेज के शिक्षक व कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई है। बाध्य होकर आंदोलन का रुख अखिबार किया गया है। मौके पर लव कुमार शुक्ला,इरफान अहमद,अर्चना कुमारी,रूपा कुमारी, रेणु कुमारी,राजीव चौबे,चंद्रशेखर शुक्ला,अनिल चौबे,उमेश सिंह,लक्ष्मीकांत शुक्ला,पनपती कुंवर,सुनीता पांडेय,अंजना कुमारी,नागेश्वर प्रसाद सहित कई कॉलेज कर्मी मौजूद थे।

30 दिसंबर को गुरी सर्वश्वरी समूह की स्थापना

विश्रामपुर पलामू/विश्रामपुर प्रखंड के गुरी गांव में 30 दिसंबर दिन शुक्रवार को सर्वेश्वरी समूह की स्थापना दिवस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम सहित अखंड कीर्तन व जरूरतमंद लोगों के बीच वस्त्र का वितरण किया जाएगा। इसकी जानकारी देते हुए सर्वेश्वरी समूह के संजीत कुमार मिश्र ने बताया कि खुली गांव स्थित श्री सर्वेश्वरी समूह प्रार्थना गृह भगवान महावराह पीठ मरहटिया श्री सर्वेश्वरी समूह शाखा आश्रम की ओर से संचालित होता है।

जिला खनन टास्क फोर्स की बैठक संपन्न,डीसी ने दिया अवैध खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी का आदेश

हर हाल में अवैध खनन रोके: डीसी

अवैध खनन करनेवालों पर प्राथमिकी दर्ज कर भेजे जेल: डीसी, जिले में अवैध माइनिंग किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं: उपायुक्त

मेदिनीनगर पलामू/जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त आंजनेयुलू दोड्डे की अध्यक्षता में सोमवार को जिला खनन टास्क फोर्स समिति की बैठक हुई। समाहरणालय के सभाकक्ष में आयोजित बैठक में जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार ने अवैध खनन पर कार्रवाई का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया। इस दौरान उन्होंने बताया कि पिछले तीन महीने में अबतक अवैध परिवहन व खनन कर रहे कुल 54 वाहनों को जन्ब किया गया है साथ ही 16 लाख 82 हजार रुपये बतौर जुमाना भी वसुला गया वहीं कुल 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज की गयी है। समीक्षा के दौरान उपायुक्त श्री

दोड्डे ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी को उनके क्षेत्र में संचालित अवैध माइनिंग के खिलाफ स्पेशल टास्क फोर्स का गठन कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने बिना सीटीआई और लाइसेंस प्राप्त किए जिले में संचालित क्रेशर को सील करने का भी निर्देश दिया। जिससे जिले में अवैध खनन के साथ-साथ प्रदूषण पर भी नियंत्रण किया जा सके। उन्होंने जिला खनन पदाधिकारी एवं सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को आपस में समन्वय बनाकर अवैध माइनिंग के विरुद्ध छापामारी करने कि बात कही। उन्होंने कहा कि जिले में कहीं भी किसी तरह के अवैध माइनिंग को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

उन्होंने ओवरलोडिंग कर रहे वाहनों को अविलंब रूप से जप्त करने व जुमाना वसूलने के बाद ही छोड़ने की बात कही। उन्होंने थाना प्रभारी व सीओ को संयुक्त रूप से बालू का अवैध खनन में रोकने हेतु अपना योगदान देने की बात कही।

बैठक में ये रहे मौजूद
बैठक में उपायुक्त दोड्डे के अलावा पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार सिन्हा, वन प्रमंडल पदाधिकारी,अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह,सदर अनुमंडल पदाधिकारी राजेश साह,छतरपुर अनुमंडल पदाधिकारी एनके गुप्ता,हुसैनाबाद अनुमंडल पदाधिकारी कमलेश्वर नारायण, जिला खनन पदाधिकारी आनंद कुमार वन एवं प्रदूषण विभाग के कर्मी उपस्थित थे।

विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने को लेकर उपायुक्त ने पदाधिकारियों संग बैठक की

मेदिनीनगर पलामू/मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में दिये गये निर्देशों का जिले में शतप्रतिशत अनुपालन करवाने को लेकर उपायुक्त सह जिलादंडाधिकारी आंजनेयुलू दोड्डे ने सोमवार को सभी बीडीओ-सीओ व विभिन्न विभागों के पदाधिकारियों संग बैठक की। समाहरणालय के सभागार में आयोजित बैठक में उपायुक्त ने किशोरी समुद्धि योजना,मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना,पशुधन योजना,सुखाड़ राहत,सहित

विभिन्न प्रकारों की छात्रवृत्ति योजना समेत मनरेगा से संबंधित योजनाओं की एक-एक कर समीक्षा की।इस दौरान उन्होंने समाज कल्याण पदाधिकारी को किशोरी समुद्धि योजना अंतर्गत अब तक प्राप्त आवेदनों का वेरिफिकेशन के पश्चात बचिच्यों के खाते में राशि भेजने की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया साथ ही सभी बीडीओ को शेष आवेदनों को जिला समाज कल्याण में भेजने की बात कही। इसी तरह पशुपालन विभाग की समीक्षा के दौरान

उपायुक्त ने पशुपालन पदाधिकारी को जेएसएलपीएस के डीपीएम के साथ समन्वय में बनाते हुए बतख पालन के लाभुकों की संख्या बढ़ाने हेतु निर्देश दिया गया। उन्होंने छात्रवृत्ति के संबंध में जिला शिक्षा पदाधिकारी व जिला कल्याण पदाधिकारी को आपस में बैठक करने व छात्रवृत्ति से संबंधित समस्याओं का निराकरण करते हुए बच्चों के खातों में राशि भेजने की कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया।वहीं मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना अंतर्गत

अंचल स्तर पर आवेदनों का वेरिफिकेशन में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने इसमें तेजी लाने पर बल दिया। इसी क्रम में मनरेगा संचालित योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। मौके पर उप विकास आयुक्त रवि आनंद,अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, प्रशिक्षु आईएएस श्रीकांत विसपुते, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शब्बीर अहमद,तीनों एसडीओ, बीडीओ, सीओ समेत जिला स्तरीय अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे।

पलामू की समस्या को लेकर सबे के परिवहन मंत्री चम्पई सोरेन से मिले युवा समाजसेवी अरविंद गुप्ता चुनमुन

मंत्री से की दुर्घटना में दिवंगत युवाओं के परिजनों के लिए मुआवजे की मांग

छतरपुर पलामू : झारखंड मंत्रिमंडल में परिवहन, अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग कल्याण के कैबिनेट मंत्री चम्पई सोरेन से छतरपुर के युवा समाजसेवी सह नगर के अध्यक्ष पद के भावी प्रत्याशी अरविंद गुप्ता चुनमुन ने विधानसभा में मुलाकात की। उन्होंने मंत्री को बताया कि गत महीनों पूर्व बिहार के नबीनगर इलाके में सड़क दुर्घटना में छतरपुर के पांच युवकों की मौत घटनास्थल पर ही हो गयी थी। दिवटर पर अरविंद गुप्ता द्वारा सूचना देने के बाद विभागीय मंत्री ने तत्कालीन पलामू डीसी को मदद करने का निर्देश भी दिया था लेकिन अभी तक मुतकों के परिजनों को कोई मदद जिला प्रशासन के द्वारा नहीं मिली है। श्री अरविंद ने मंत्री चम्पई सोरेन को पांच युवकों को मुआवजे की याद दिलाई। इस पर मंत्री ने अधिकारियों से जानकारी ले कर कार्रवाई करने की बात कही। साथ ही साथ अरविंद ने उन्हें यह भी बताया कि छतरपुर के कई लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हुई है जिसका मुआवजा अभी तक जिला मुख्यालय में वर्षों से पेंडिंग है, परिजनों को आवंटन न होने की बात बताई जाती है भुगतान करवाने का आग्रह भी मंत्री से किया गया मंत्री ने आस्वस्त किया कि वे डीसी से भुगतान लिए बात करेंगे।

बीडीओ ने उसुलाई जनवितरण प्रणाली दुकान का किया निरीक्षण,दिया वलीन चिट विश्रामपुर पलामू/विश्रामपुर बीडीओ सह प्रभारी एमओ प्रशांत कुमार हेंब्रम ने नप के वार्ड दस अंतर्गत उसुलाई गांव के जन वितरण प्रणाली दुकान का निरीक्षण किया। जांच के दौरान आवंटन,भंडारण व वितरण सभी कुछ सही पाया गया। जिसके बाद बीडीओ ने डीलर मालका आरा बीबी को वलीन चिट देते हुए नवंबर माह के खाद्यान को वितरित करने का निर्देश दिया। माधुरीडीह गांव के कुछ ग्रामीणों ने डीलर मालका आरा बीबी पर खाद्यान वितरण में अनियमितता बरतने का आरोप लगाया था। ग्रामीणों ने इसकी लिखित शिकायत बीडीओ से की थी। ग्रामीणों के शिकायत के आलोक में ही बीडीओ प्रशांत कुमार हेंब्रम ने इस पीडीएस दुकान का निरीक्षण किया।

इप्टा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन, आओ कि कोई ख्वाब बुनें कल के वास्ते इप्टा राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए विभिन्न उप समितियों का हुआ गठन

मेदिनीनगर पलामू

इप्टा का 15वां राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 में 17 से 19 मार्च तक पलामू जिला के रणवीर सिंह महानगर डालनगंज होने जा रहा है। राष्ट्रीय सम्मेलन की तैयारी हेतु एक व्यापक स्वागत समिति बनाई गयी है, जिसके स्वागताध्यक्ष डॉ अरुण शुक्ला, कार्यकारी अध्यक्ष प्रेम भसीन और महासचिव शैलेंद्र कुमार हैं। इसके अलावा संयुक्त के संस्कृक्त मंडल में झारखंड के लोक कलाकार परमश्री मधु मंसूरी, साहित्यकार डॉ रणमणि, सामाजिक कार्यकर्ता दयानिध बरला, आकाशवाणी-दूरदर्शन की निदेशिका मेरी क्लौडिया



सोरेंग, कथाकार पंकज मित्र, लेखक डॉ मिथिलेश, समाजसेवी ज्ञानचंद पांडे, सुरेश जैन, नवल तुलस्यान, जयशंकर चौधरी, इब्रार अहमद, डॉ वनजा शुक्ला, आलोक वर्मा और केडी सिंह का नाम शामिल है। रविवार को रेडमा स्थित इप्टा कार्यालय में स्वागत समिति

की बैठक प्रेम भसीन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में राष्ट्रीय सम्मेलन को सफल बनाने के लिए बनाई गई आयोजन समिति के अलावा अलग-अलग उप समितियों का भी गठन कर जवाबदेही सौंपी गई। इसके लिए वित्त उपसमिति, सांस्कृतिक कार्यक्रम उपसमिति, भोजन,

आवास व वाहन उपसमिति, प्रचार-प्रसार उप समिति, ग्रांडंज व हॉल उप समिति, चिकित्सा उपसमिति और महिला उपसमिति का गठन किया गया है, जिसमें अलग-अलग लोगों को जिम्मेवारी सौंपी गई है। बैठक के दौरान स्वागत अध्यक्ष डॉ शुक्ला ने कहा कि पलामू जिला में इप्टा

का राष्ट्रीय सम्मेलन ऐतिहासिक होगा। सम्मेलन का थीम साहिर लुधियानवी की मशहूर नज्म आओ कि कोई ख्वाब बुनें कल के वास्ते.. रखा गया है जो अपने आप में यह बताने के लिए काफ़ी है कि इप्टा सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। सम्मेलन में देश भर से 500 से अधिक कलाकार व संस्कृति कर में हिस्सा लेंगे। तीन दिनों तक शिवाजी मैदान में अखिल भारतीय सांस्कृतिक समारोह का भी आयोजन किया जाएगा। जिसमें हिंदुस्तान के विविध लोक कला और साझी सांस्कृतिक विरासत की झलक पलामूवासियों को देखने को मिलेगी।

निकाला गया जो शहर भर का भ्रमण करते हुए वापस अपने गंतव्य को पहुंचा। इसका विशेष प्रशिक्षण अर्थात ट्रेनिंग पांच दिवसीय यूटीसी कैंप में त्वागी तपस्वी व अनुभवी प्रउत विशेषज्ञ के द्वारा अध्यात्म विज्ञान व आर्थिक दर्शन, सामाजिक दर्शन-प्रउत तर्कसंगत, युक्तिसंगत व विज्ञानसंगत दी गई। समापन के उपरांत आनंद मार्ग पलामू की महिला विंग के द्वारा डालटनगंज रेलवे स्टेशन पर नारायण सेवा किया गया इस दौरान सैकड़ों भूखे लोगों को भोजन कराया गया। मौके पर भुक्ति प्रधान महेश्वर, प्रउत भुक्ति प्रधान मणिकांत, आचार्य शुभगतानन्द अवधूत, आचार्य कृष्णसुंदरानन्द अवधूत, आचार्य सिद्धविद्यानन्द अवधूत, आचार्य सिद्धार्थ आनंद अवधूत, अवधूतिका कृतिमया दीदी, सरोज, गोपाल, अरविंद, मंगल, शारदा, चांदनी, आदि उपस्थित थे।



पदाधिकारी आनंद कुमार वन एवं प्रदूषण विभाग के कर्मी उपस्थित थे।

जसपुर के लाभुको ने आशा महीला विकाश समूह पर लगाया मनमानी का आरोप

पांकी पलामू/पलामू जिले के पांकी प्रखंड के लोहरसी पंचायत के जसपुर गांव के लाभुको ने आशा महीला विकाश समूह पर कम राशन देने का आरोप लगाया है। आशा महीला विकाश समूह के द्वारा लाभुकों को निर्धारित मात्रा से कम राशन देने से लाभुको में आक्रोश है। सोमवार को बड़ी संख्या में लाभुकों ने इसका विरोध किया। ग्रामीणों ने बताया कि आशा महीला विकाश समूह द्वारा लाल या पीला कार्ड सभी मामले में मनमानी करते हैं। केंद्र सरकार के गरीब कल्याण योजना के तहत भी राशन वितरण में मनमानी किया जाता है। पीला राशन कार्ड धारियों ने कहा कि उन्हें निर्धारित मात्रा से 35 किलो के जगह 30 किलो 5 किलो कम राशन दिया जाता है। इसी तरह लाल कार्ड धारियों को भी प्रति यूनिट 5 किलो की जगह साढ़े 4 किलो ही राशन दिया जाता है। केंद्र सरकार की गरीब कल्याण योजना के तहत भी उन्हें निर्धारित मात्रा से कम राशन दिया जाता है। मौके पर ग्रामीण सबीना बीबी, हाजरा बीबी, शावदा बीबी, गुलशन बीबी, रिमना बीबी, इमाम अली, अख्तर अंसारी, बदरुद्दीन अंसारी, हनीफ मिया इत्यादि लोगों ने कहा कि आशा महीला विकाश समूह को जसपुर में राशन वितरण करना था लेकिन अपने घर में ही राशन वितरण करता है। और सभी लाभुकों को राज्य सरकार और केंद्र सरकार से दिए जा रहे राशन में भी कटौती किया जाता है। इस संबंध में एमओ सह सीओ निर्भय कुमार से दुर्भाष से संपर्क करने की प्रयास किया गया तो उन्होंने कॉल रिसीव नहीं किए और संपर्क नहीं हो पाया।

एम एस सी एच मेदनीनगर मे फैले कुयवस्था के खिलाफ आजसू पार्टी का प्रतिनिधि मंडल, उपायुक्त पलामू ए दौड़े से मिलकर ज्ञापन सीपा

मेदनीनगर पलामू/एम एस सी एच के संदर्भ में कहना है कि मेदनीनगर एम एस सी एच पलामू प्रमंडल में एक मात्र चिकित्सा संस्थान हैं जिस पर गरीब जनता के चिकित्सा व्यवस्था निर्भर है। मगर चिकित्सा पदाधिकारी व कर्मचारियों की घोर लापरवाही है। पहली बात है कि बायोमेट्रिक के द्वारा सभी का उपस्थिति दर्ज होती है, मगर इसका घोर उलंघन हो रहा है, चिकित्सक सप्ताह में एक बार बायोमेट्रिक से उपस्थिति दर्ज कराते हैं और एक सप्ताह तक लपता रहते हैं। अपने निजी प्रेक्टिस मे लगे रहते हैं ऐसा ही हाल कर्मचारियों का है। दुसरी बात रोस्टर के अनुसार इयुटी बटती है तीन चिकित्सक को रात्री मे इयुटी लगती है। मगर केवल एक डाक्टर ही उपलब्ध रहते हैं। अतः महोदय से आग्रह पुर्वक निवेदन है कि इसे उच्च स्तरीय जांच करा कर इस अनियमितता पर रोक लगाई जाए।

जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण

विश्रामपुर पलामू/विश्रामपुर प्रखंड अंतर्गत बघमनवा पंचायत के घरटीया गांव में आदिवासी खरवार लोकसेवक संघ व खरवार एकता संघ के द्वारा संयुक्त रूप से 200 जरूरतमंदों के बीच कंबल का वितरण किया गया। जरूरतमंद गरीब व वृद्धों के बीच कंबल का वितरण बतौर मुख्य अतिथि विश्रामपुर थाना प्रभारी शशि रंजन व खरवार एकता संघ के जिलाध्यक्ष

सर्कस की शूटिंग को लेकर रणवीर ने खोले कई राज

-एक्टर ने बताया-कैसे उन्होंने इस फिल्म में काम किया

अपनी फिल्म सर्कस की शूटिंग को लेकर बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने कई सारे राज खोले। उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने रोहित शेट्टी की इस फिल्म में काम किया। रणवीर सिंह ने कहा इस फिल्म में करंट लगने वाली स्थिति की रोहित शेट्टी ने हमको बहुत सारी रिहर्सल कराई थी क्योंकि वह चाहते थे कि सीन बहुत साधारण हो क्योंकि यह एक ऐसा सीन है जिसको करने के लिए बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी पड़ती हैं। आगे रणवीर ने कहा रोहित शेट्टी बहुत ही साधारण और वास्तव बनाना चाहते थे इसीलिए हमने बहुत मेहनत की। यह बिजली का करंट लगने वाला सीन इतना आसान नहीं था कि बस हम जाएं इलेक्ट्रिसिटी का तार पकड़ें और समझ जाएं कि कैसे एक्टिंग करनी है। बल्कि मैंने इसके लिए बहुत सारे तरीके अपनाए तब जाकर यह सीना किया। इसके साथ ही अभिनेता ने रोहित शेट्टी की और उनके फिल्म बनाने के कौशल भी तारीफ की साथ ही कहा कि यह फिल्म सर्कस लोगों को बहुत पसंद आएगी। बता दें कि फिल्म के प्रमोशन के लिए द कपिल शर्मा शो पर अपनी टीम के साथ पहुंचे रणवीर सिंह ने इस फिल्म को लेकर कई सारी बातों की और अपने अनुभव साझा किए।



याई रे में हनी सिंह ने डाला ईडीएम का तड़का

1990 के दशक की हिट फिल्म रंगीला का सुपरहिट ट्रैक याई रे को रैपर यो यो हनी सिंह ने रीक्रिएट किया है जो ग्रैमी और ऑस्कर विनर कपोजर ए.आर. रहमान का पहला हिंदी साउंडट्रैक था। रीक्रिएटेड नंबर में ईडीएम (इलेक्ट्रॉनिक डांस म्यूजिक) है जो इसे एक पार्टी एंथम बनाती है। गाने में यूलिया वतूर को एक नए अवतार में दिखाया गया है। गाने के बारे में बात करते हुए हनी सिंह ने कहा मुझे ओरिजिनल सॉन्ग याई रे बहुत पसंद आया और जब इस तरह के आइकोनिक ट्रैक को फिर से बनाने का अवसर आया तो मैं इसे करने के लिए फौरन तैयार हो गया। याई रे 2022-2023 का पार्टी एंथम है। हमें उम्मीद है कि फैस इसे उतना ही पसंद करेंगे जितना इसके ओरिजिनल थीम को किया गया था। म्यूजिक वीडियो मिहिर गुलाटी द्वारा निर्देशित है जिन्होंने हनी सिंह के साथ कई प्रोजेक्ट्स पर काम किया है। वीडियो एक क्लब में सेट किया गया है जहां हनी और यूलिया दोनों को बिल्कुल नए याई रे के हुक-स्टेप पर डांस करते हुए दिखाया गया है।



फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी लॉन्च करके दीपिका पादुकोण ने देश को किया गौरवान्वित

फीफा वर्ल्ड कप 2022 का मुकाबला फ्रांस और अर्जेंटीना के बीच खेला गया। अर्जेंटीना ने 38 साल बाद फीफा वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम की। इस फाइनल मुकाबला देखने के लिए कई भारतीय सितारे भी दुबई पहुंचे थे। वहीं भारत को गौरवान्वित करते हुए दीपिका पादुकोण फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी से पदार्पण वाली पहली भारतीय बनीं। 6.175 किलोग्राम और 18 कैरेट सोने और मैलाकाइट से बनी इस ट्रॉफी को केवल कुछ खास लोगों द्वारा ही छुआ और पकड़ा जा सकता है, जिसमें फीफा वर्ल्ड कप के पूर्व विजेता और हेड्स ऑफ स्टेट शामिल हैं। ऐसे में दीपिका पादुकोण सहित पूरे भारत के लिए ये बेहद खास पल बना। दीपिका पादुकोण लक्जरी कपड़ों और एक्सेसरीज ब्रांड लुईस वुइटन की ग्लोबल एंबेसेडर हैं। लुईस वुइटन 2010 से फीफा वर्ल्ड कप के पार्टनर हैं। फुटबॉल वर्ल्ड कप के सपोर्ट की वजह से इसकी ग्लोबल एंबेसेडर दीपिका पादुकोण को फाइनल से पहले ट्रॉफी का अनावरण करने के लिए चुना गया था। वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस और डांसर नोरा फतेही ने फीफा विश्व कप 2022 के फाइनल मुकाबले के ठीक पहले व्लोजिंग सेरेमनी में अपनी दमदार परफॉर्मेंस दी। नोरा फीफा की व्लोजिंग सेरेमनी में परफॉर्म करने वाली एकमात्र भारतीय स्टार रही।

जानिए कब शादी करेंगे प्रभास, सलमान खान से है कनेक्शन

साउथ सुपरस्टार प्रभास ने फिल्म 'बाहुबली' से दुनियाभर में जबरदस्त पहचान बनाई है। प्रभास जल्द ही फिल्म 'आदिपुरुष' में नजर आने वाले हैं। इन दिनों एक्टर का नाम इस फिल्म की को-एक्ट्रेस कृति सेनन संग जुड़ रहा है। हालांकि कृति सेनन ने इन खबरों को अफवाह बताया है। वहीं अब प्रभास ने अपने वेंडिंग प्लान का खुलासा किया है। प्रभास ने एक तेलुगु टॉक शो में अपनी शादी को लेकर बात की। शो के होस्ट नंदामुरी बालकृष्ण ने प्रभास से पूछा कि हाल ही में जब सर्वानंद शो में आए तो मैंने उनसे उनकी शादी के बारे में पूछा तो उनका जवाब था कि वो आपके बाद शादी करेंगे, तो अब आप बताएं कि आप शादी कब करेंगे। इस सवाल के जवाब में प्रभास ने कहा कि अगर सर्वानंद ने कहा है कि वो मेरे बाद शादी करेंगे, तो मुझे कहना चाहिए कि मैं सलमान खान के बाद शादी करूंगा। फैस प्रभास के इस जवाब की खूब तारीफ कर रहे हैं। बता दें कि प्रभास जहां 43 साल के हो गए हैं वहीं सलमान खान 56 साल के हैं। अब प्रभास को दुल्हा बने देखने के लिए फैस को सलमान खान की शादी का इंतजार करना होगा।



सारा अली खान ने पूरी की 'ऐ वतन मेरे वतन' की शूटिंग

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने काफी कम वक्त में इंडस्ट्री में एक अलग पहचान बनाई है। एक्ट्रेस जल्द ही %ऐ वतन मेरे वतन% में नजर आने वाली हैं। सारा अली खान की यह फिल्म सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज होगी। सारा अली खान %ऐ वतन मेरे वतन% में स्वतंत्रता सेनानी की भूमिका में नजर आएंगी। सारा, उषा मेहता के किरदार में नजर आएंगी। %ऐ वतन मेरे वतन% धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले बनाई जा रही है। इस फिल्म को कन्नन अख्यर ने निर्देशित किया है वहीं, फिल्म की कहानी दरब फारुकी ने लिखी है। सारा अली खान ने अपनी इस फिल्म की शूटिंग पूरी होने की जानकारी अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर तस्वीरें साझा कर दी हैं। सारा अली खान ने तस्वीरें साझा कर बताया कि वह बीते कई दिनों से ऐ वतन मेरे वतन के लिए नाइट शूटिंग की शूटिंग कर रही थीं, लेकिन रविवार को उन्होंने अपने इस शूटिंग को पूरा कर लिया है। इस तस्वीर में एक कैक भी नजर आ रहा है, जिसमें पर लिखा है इट्स रेप। साथ ही उन्होंने तस्वीर में ऐ वतन मेरे वतन भी लिखा है। गौरतलब है कि उषा मेहता स्वतंत्रता संग्राम के दौरान सीक्रेट रेडियो ऑपरेटर थीं। उन्होंने देश की स्वतंत्रता के दौरान अहम भूमिका निभाई थी। उषा मेहता ने सीक्रेट रेडियो सर्विस %कांग्रेस रेडियो% की शुरुआत की थी। इस सर्विस रेडियो की मदद से उस समय वह सारी जानकारी और अन्य खबरें शेयर की जाती थीं, जिस पर उस दौरान अंग्रेजों ने पाबंदी लगा रखी थी।



गोविंदा नाम मेरा के गाने पर थिरके युगांडा के बच्चे

बॉलीवुड स्टार विकी कौशल और कियारा आडवाणी की फिल्म गोविंदा नाम मेरा के गाने क्या बात है 2.0 पर युगांडा के बच्चे थिरकते नजर आए। इन बच्चों का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर सामने आया जो कि उन बच्चों के पेज पर था। इसमें कैप्शन में लिखा था लिव लव लाफ...टूडे। इसके बाद इस वीडियो को दोबारा कियारा आडवाणी ने भी अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर साझा किया और कैप्शन में लिखा टू गुड। शांशाक खेतान द्वारा लिखी गई फिल्म गोविंदा नाम मेरा एक कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। इस फिल्म में मुख्य भूमिका में विकी कौशल कियारा और भूमि पेडनेकर भी हैं। बता दें कि यह युगांडा के एक एनजीओ के कुछ बच्चे एक साथ मिलकर विकी कौशल और कियारा आडवाणी ने भी डांस किया।

एयर होस्टेस बनना चाहती थीं अंकिता लोखंडे यूं बन गई एक्ट्रेस

अंकिता लोखंडे टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी एक अलग पहचान बना चुकी हैं। अंकिता 19 दिसंबर को अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं। एक्ट्रेस का जन्म? 1984 में इंदौर में एक मराठी परिवार में हुआ था। अंकिता का असली नाम तनुजा लोखंडे हैं। इंदौर से ही अपनी पढ़ाई पूरी करने वाली अर्चना को कभी भी अभिनय की दुनिया में आने की रुचि नहीं थी। अंकिता का परिवार भी नहीं चाहता था कि वह एक्ट्रेस बने। ऐसे में जब अंकिता ने छोटे पर्दे से अपने करियर शुरुआत की, तो परिवार ने उन्हें सपोर्ट भी नहीं किया था। अंकिता लोखंडे ने एयर होस्टेस बनने के लिए फैंकफिन एकेडमी ज्वाइन कर ली थी, लेकिन इसी बीच इंदौर में जी सिनेस्टार की खोज शुरू हुई और अंकिता को चुन लिया गया। इसके बाद साल 2005 में अंकिता मुंबई शिफ्ट हो गई। अंकिता ने मुंबई आकर मॉडलिंग की दुनिया में कदम रखा। इसके बाद उन्हें 'बाली उग्र को सलाम' शो से डेब्यू करने का मौका मिला। हालांकि यह शो कभी ऑन एयर नहीं हुआ। इसके बाद अंकिता लोखंडे को एकता कपूर के 'पवित्र रिश्ता' में काम करने का मौका मिला। इस शो में उनके किरदार अर्चना को खूब पसंद किया गया और अंकिता घर-घर लोकप्रिय हो गई। इसके बाद वह 'झलक दिखला जा 4' में नजर आईं। अंकिता लोखंडे ने 2019 में कंगना रनौट की फिल्म 'मणिकर्णिका' से बॉलीवुड डेब्यू किया। वह टाइगर श्रॉफ की फिल्म 'बागी 3' में भी नजर आ चुकी हैं।



एलन मस्क ने ट्विटर के सीईओ का पद छोड़ने पर कराया पोल, ये आया जवाब

लंदन। एलन मस्क और उनका टिवटर झामा कभी खत्म नहीं होने वाला लगता है। मस्क ने टिवटर का सहारा लेते हुए एक पोल के जरिये उपयोगकर्ताओं से पूछा कि क्या उन्हें कंपनी के प्रमुख के रूप में पद छोड़ना चाहिए। मस्क ने विकल्पों के लिए हां और नहीं का ऑप्शन दिया। वोटिंग समाप्त हो गया है और परिणाम आ गया है। पोल के अनुसार, टिवटर उपयोगकर्ता चाहते हैं कि मस्क टिवटर प्रमुख के पद से हट जाए। लगभग 57.5 प्रतिशत टिवटर उपयोगकर्ताओं ने मस्क के पद छोड़ने के लिए मतदान किया, जबकि 42.5 प्रतिशत अभी भी चाहते हैं कि वह कंपनी का नेतृत्व करें। 1.7 करोड़ से अधिक टिवटर यूजर्स ने पोल में अपने विचार साझा किए। अब, सवाल यह है – क्या मस्क वास्तव में कंपनी के प्रमुख के रूप में पद छोड़ देंगे, या पोल सिर्फ एक और पब्लिसिटी स्टंट है। इसका पता तो आने वाले वक्त में ही चलेगा। मस्क वर्तमान में बोर्ड के एकमात्र सदस्य के रूप में सेवा दे रहे हैं और उनके नेतृत्व में टिवटर पर सभी टीमों की बारीकी से निगरानी भी कर रहे हैं। अखण्पति ने अक्टूबर में टिवटर बॉस का पदभार संभालते ही अधिकांश शीर्ष अधिकारियों को निकाल दिया, जिनमें पूर्व सीईओ पराग अग्रवाल, कानूनी प्रमुख विजय गहू और कई अन्य शामिल थे। अग्रवाल को सीईओ के पद से हटाने के तुरंत बाद मस्क ने कहा था कि वह टिवटर के फ़्रअस्थायी सीईओफ़्र के रूप में तब तक काम करेंगे जब तक कि उन्हें कोई प्रतिस्थापन नहीं मिल जाता। बाद में मस्क ने कहा कि वह टिवटर के लिए नए सीईओ की तलाश कर रहे हैं। अब इन घटनाओं को देखते हुए माना जा रहा है कि मस्क टिवटर के सीईओ का पद संभालने के लिए अपने किसी करीबी को पाते ही टिवटर प्रमुख के पद से हट जाएंगे। ऐसा लगता है कि मस्क को अभी भी टिवटर के सीईओ पद के लिए कोई नहीं मिला है।

दानी हिसवानी ने सिर पर 9 फीट ऊंची हेयरस्टाइल बनाकर बनाया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड

दुबई। फेमस हेयरस्टाइलिस्ट दानी हिसवानी का नाम सबसे ऊंचा हेयरस्टाइल बनाने के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। हिसवानी ने दुबई में क्रिसमस टी के आकार में 9 फीट 6.5 इंच लंबा हेयरस्टाइल बनाया है। इस हेयरस्टाइल का वीडियो हाल ही में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया गया है। इस अनूठे हेयरस्टाइल की वजह से सोशल मीडिया पर लोग दानी को ट्रोल कर रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि महिला ने एक हेलमेट पहन रखा है। हेलमेट में तीन धातु के डंडे भी नजर आ रहे हैं। क्रिसमस टी जैसा हेयर स्टाइल करने के लिए दानी हिसवानी ने विग हेयर एक्सटेंशन का यूज किया। वहीं हेयरस्टाइल करते हुए बॉल्स का भी उपयोग किया। वीडियो का कैप्शन है दानी हिसवानी द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा हेयरस्टाइल—9 फीट 6.5 इंच। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक दानी फेशन की दुनिया में पिछले सात साल से हैं। खुद दानी हेयरस्टाइलिंग को पेशा न मानते हुए एक कला के तौर पर देखते हैं। दानी ने इससे पहले एक महिला के सिर पर हेयरस्टाइलिंग करते हुए एक छोटा क्रिसमस टी बनाया था इस बार उन्होंने सबसे ऊंचा हेयरस्टाइल बनाने का चैलेंज लिया। वीडियो को इंस्टाग्राम पर 3 लाख से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं। हालांकि कई इंटरनेट यूजर्स इस रिकॉर्ड और हेयरस्टाइल को देखकर खुश नजर नहीं आए। एक यूजर ने लिखा कि यह हेयरस्टाइल नहीं है बल्कि यह हेडस्टेस है। एक तीसरे यूजर ने लिखा कि हेयरस्टाइल में तो महिला के खुद के बालों का उपयोग होना चाहिए था इस तरह गिनीज रिकॉर्ड बन जाना तो पूरी तरह बिजनेस कॉन्सपेट को दिखाता है।

पाक : उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में आतंकवादी हमले में चार पुलिसकर्मियों की मौत

पेशावर। पाकिस्तान के अशांत खैबर पख्तुनख्वा प्रांत में रविवार को एक नवनिर्मित पुलिस थाने पर हुए आतंकवादी हमले में कम से कम चार पाकिस्तानी पुलिसकर्मी मारे गए और चार अन्य घायल हो गए। पुलिस ने बताया कि दक्षिण वजीरिस्तान कबाइली जिले की सीमा से लगे लकी मारवात स्थित बराई पुलिस थाने पर आतंकवादियों ने हमला किया। आतंकवादियों के पास हथगोल और रॉकेट लांचर सहित अन्य घातक हथियार थे। पुलिस के साथ मुठभेड़ के बाद सदियुग आतंकवादी मौके से फरार हो गए। सदियुगों को पकड़ने के लिए पुलिस ने इलाके में तलाशी अभियान चलाया। खैबर पख्तुनख्वा प्रांत के मुख्यमंत्री महमूद खान ने हमले को कायरतापूर्ण कृत्य बताया और प्रांतीय पुलिस प्रमुख से तत्काल रिपोर्ट मांगी। राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने भी शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की और हमले की निंदा करते हुए कहा, फ़आतंकवाद के पूरी तरह से सफाये तक हमारे प्रयास जारी रहेंगे। हालांकि, किसी भी समूह ने तत्काल हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। जिले में पुलिसकर्मियों पर हुए पिछले हमलों की जिम्मेदारी तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान (टीटीए) ने ली है।

ब्रिटेन में एंबुलेंस चालकों की हड़ताल भेजे जाएंगे 1200 सैनिक

लंदन। ब्रिटिश सरकार ने कहा कि एंबुलेंस चालकों और अन्य कर्मियों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर वह 1200 जवानों को तैनात करेगी। ब्रिटेन में आगामी क्रिसमस से पहले के हफ्ते में कई सार्वजनिक क्षेत्र के यूनियन काम से दूर रहेंगे। एंबुलेंस चालकों की हड़ताल बुधवार को प्रस्तावित है जिसमें नर्स रेलवे स्टाफ पासपोर्ट अधिकारी और डाककर्मी शामिल हो रहे हैं। ब्रिटेन में दशकों की इस सबसे अधिक असह्यदार हड़ताल की लहर को खाद्य पदार्थों और ऊर्जा कीमती की बढ़ती कीमत के कारण उपजे गुजर-बसर समकट के प्रति लोगों की प्रतिक्रिया के रूप में देखा जा रहा है। कोविड-19 महामारी और यूक्रेन पर रूस के हमले के मद्देनजर महंगाई बढ़ी है। इससे पहले अक्टूबर में हड़ताल के कारण 417000 कार्य दिवस का नुकसान हुआ जो एक दशक में सर्वाधिक संख्या है। कर्मचारी यूनियन महंगाई के अनुरूप वेतन में बढ़ोतरी की मांग कर रही हैं जो नवंबर में 10.7 फीसदी थी। हालांकि महंगाई दर अक्टूबर में 11.1 फीसदी पर पहुंच गई थी जो 40 सालों में सर्वाधिक है। नर्सों और एंबुलेंस चालकों ने कहा कि हड़ताल के दौरान वे अभी आपतकालीन सेवाओं में सहयोग कर रहे हैं।

स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के चलते पोप फ्रांसिस ने लिखा था त्यागपत्र

– पोप फासिस 86 वर्ष के हो गए उन्होंने 2021 में आंत से जुड़ी समस्या के लिए सर्जरी कराई थी

रोम। पोप फ्रांसिस ने हाल ही में एक साक्षात्कार में खुलासा किया है कि 2013 में पोप चुने जाने के ठीक बाद उन्होंने त्यागपत्र लिखा था ताकि स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के कारण अपने कर्तव्य के निर्वहन में बाधा आती की स्थिति में वह पद छोड़ सकें। स्पेन के एक अखबार से फ्रांसिस ने कहा कि उन्होंने कार्डिनल तारकिसियो बर्टोन को यह नोट दिया था जो उस समय वैटिकन के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे। पोप ने कहा कि वह मानते हैं कि वर्तमान में वैटिकन के नंबर 2 की भूमिका में कार्डिनल पिअ्रो पारोलिन के पास यह लिखित निर्देश मौजूद है। वैटिकन का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट आम तौर पर राजनीतिक और कूटनीतिक दायित्वों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। पोप फ्रांसिस 86 वर्ष के हो गए। उन्होंने 2021 में आंत से जुड़ी समस्या के लिए सर्जरी कराई थी। घुटने के दर्द से परेशानी के कारण भी उन्होंने कत उन्हे व्हीलचेयर का इस्तेमाल करते देखा गया था। हालिया दिनों में उन्होंने सार्वजनिक रूप से घूमने के लिए व्हीलचेयर के बजाय बैत का इस्तेमाल किया।

पोप ने कहा कि मैंने पहले ही अपने त्यागपत्र पर हस्ताक्षर कर दिया है। उन्होंने कार्डिनल बर्टोन को भेजे त्यागपत्र में कहा कि मैंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं यदि मैं चिकित्सा कारणों से या किसी भी कारण से अस्वस्थ हो जाता हूं तो यह मेरा इस्तीफा है। बर्टोन अक्टूबर 2013 में सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पद से हट गए थे। उस समय फासिस को पोप बने एक महीना ही हुआ था। फ्रांसिस ने कहा कि उन्हें यकीन है कि बर्टोन ने पत्र को वर्तमान सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पारोलिन को भेज दिया होगा। इससे पहले फ्रांसिस ने अपने पूर्ववर्ती पोप बेनेडिक्ट सोलहवें की सराहना की थी क्योंकि उन्होंने बढ़ती उम्र के कारण इस्तीफा देते हुए कहा था कि वह अपने दायित्वों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर पाएंगे। बेनेडिक्ट पिछले 600 साल में इस्तीफा देने वाले पहले पोप थे। वह वैटिकन में ईसाई धर्म में रहते हैं। बेनेडिक्ट के इस्तीफे से फ्रांसिस के पोप बनने का मार्ग प्रशस्त हुआ था जो दक्षिण अमेरिका से पहले पोप हैं।



यूनान के एथेंस में क्रिसमस ट्री पर परियों की वेशभूषा में नजर आयीं दो लड़कियां।

ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक क्रिसमस हड़ताल से निपटने के लिए सैनिकों का इस्तेमाल करेंगे

लंदन (एजेंसी)। प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने रविवार को क्रिसमस की छुट्टियों में हड़ताल करके लाखों लोगों को कष्ट देने के लिए ट्रेड यूनियनों की अलोचना की। ब्रिटेन में हड़ताल का आयोजन अगले कुछ हफ्तों के दौरान किया जाना प्रस्तावित है। ब्रिटेन की सरकार ने हड़ताली कर्मियों को भरपाई के लिए 1200 जवानों को तैनात करने की योजना का ऐलान किया है ताकि जरूरी सेवाएं जारी रहें। प्रस्तावित हड़ताल में भाग लेने वालों में रेलवे कर्मी, स्वस्थ्यकर्मी, सीमा सुरक्षा स्टाफ शामिल है। यूनियनमें वेतन बढ़ाने और काम की दशाएं अच्छी करने की मांग कर रही है।

‘द सन ऑन संडे’ में रविवार को सुनक ने एक लेख में कहा कि कर्मचारियों को एक उचित और किरफायती प्रस्ताव दिया गया है। उन्होंने यूनियनों पर ‘वर्ग संघर्ष’ शुरू करने का आरोप लगाया। सुनक ने लिखा, “ यूनियन क्रिसमस को लक्ष्य करके खासकर गलत समय पर ट्रांसपोर्ट हड़ताल से लाखों लोगों को पीड़ित कर रही हैं।” सरकार ने यूनियन को बार-बार आगाह किया है कि वेतन में भारी बढ़ोतरी

की उनकी मांग को मानने से ब्रिटेन मुद्रास्फीति के भंवर में फंस जाएगा जिसका सबसे गरीब लोगों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा।

प्रधानमंत्री ने कहा कि विपक्षी दल लेबर ने भी माना है कि यूनियन की मांग पूरी नहीं की जा सकती। सुनक ने कहा, ‘हम यह सुनिश्चित करने के लिए सब कुछ कर रहे हैं कि लोगों को क्रिसमस पर वह मिल सके जिसके वे हकदार हैं। सेना आगे आई है और सेवाओं को यथा संभव जारी रखने के लिए हम अन्य उपायों को अपना रहे हैं।’ इस बीच कई यूनियन के प्रमुखों ने आगाह किया है कि सेना एंबुलेंस चलाने या देश की सीमा की रक्षा करने के लिए पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं है और उन्हें इस ‘मुश्किल’ स्थिति में नहीं खलना चाहिए। इस बीच नर्सों ने धमकी दी है कि यदि मंत्रियों ने अगले हफ्ते के बहिष्कार के बाद 48 घंटों में समाधान नहीं ढूंढा तो नये साल में और व्यापक पैमाने पर हड़ताल की जाएगी। एंबुलेंस चालकों की हड़ताल बुधवार को प्रस्तावित है जिसमें नर्स, रेलवे स्टाफ, पासपोर्ट अधिकारी और डाककर्मी शामिल हो रहे है।



यांगत्से में चीन से भिड़ंत के बाद तवांग मठ के भिक्षुओं ने किया भारत का समर्थन कहा यह 1962 नहीं 2022 है



तवांग (एजेंसी)। तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच यांगत्से में झड़प के बाद बाद प्रसिद्ध तवांग मठ के भिक्षुओं की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। तवांग मठ के भिक्षुओं ने चीन को आगाह करते हुए कहा कि यह 1962 नहीं बल्कि 2022 है और भारत में पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार है।

तवांग मठ के भिक्षु लामा येशी खावो ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को नहीं बख्शेंगे। हम मोदी सरकार और भारतीय सेना का समर्थन करते हैं। 17वीं शताब्दी के मठ में उपस्थित सभी लोगों की चिंताओं को व्यक्त करते हुए भिक्षु ने कहा कि 1962 में एशियाई दिगजों के बीच संघर्ष भी हमने देखा है।

लामा येशी खावो ने कहा कि चीनी सरकार हमेशा अन्य देशों के क्षेत्रों पर नज़रें गड़ाए रहती है यह पूरी तरह से गलत है। लामा येशी खावो ने कहा कि वह भारतीय भूमि पर भी नजर रखते हैं। चीनी सरकार गलत है। अगर वे दुनिया में शांति चाहते हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वे वास्तव में शांति चाहते हैं तो उन्हें किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। उन्होंने कहा उन्हें वर्तमान

भारत सरकार और भारतीय सेना पर पूरा भरोसा है जो तवांग को सुरक्षित रखने में पूरी तरह लक्ष्य है। तवांग मठ के भिक्षु येशी खावो ने कहा कि 1962 में हुए युद्ध के दौरान इस मठ के भिक्षुओं ने भारतीय सेना की मदद की थी। चीनी सेना भी मठ में घुस गई थी लेकिन उन्होंने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। पहले तवांग तिब्बत का हिस्सा था और चीनी सरकार ने तिब्बत की जमीन पर कब्जा कर लिया था। चीनी सरकार का दावा है कि तवांग भी तिब्बत का हिस्सा है लेकिन तवांग भारत का अन्नित्र अंग है। हमें चिंता नहीं है क्योंकि भारतीय सेना सीमा पर है। हम यहां शांति से रह रहे हैं।

भिक्षु ने कहा कि तवांग मठ 1681 में बनाया गया था जो एशिया का दूसरा सबसे बड़ा और सबसे पुराना मठ है। इसे 5वें दलाई लामा की मंजूरी के बाद बनाया गया था। छठे दलाई लामा का जन्म तवांग में हुआ था। हमें 5वें और छठे दलाई लामा का आशीर्वाद प्राप्त है। वर्तमान में तवांग मठ में लगभग 500 भिक्षु हैं। मठ के परिसर और गुरुकुल में 89 छोटे घर हैं। इसके अलावा यहां बौद्ध धर्म दर्शन के साथ-साथ सामान्य शिक्षा भी प्रदान की जाती है।

आ रहा नया साल.... फिर होगा 2019 जैसा हाल? चीन के अस्पतालों में लाखों का लगा अंबार

वॉशिंगटन (एजेंसी)। चीन जितने थोखा देने में माहिर है उतना ही सच छुपाने में भी उस्ताद है। तवांग झड़प के चीन के इसी छल का सबूत है। आखिर क्यों चीन ने एलएसी पर भारत से ब्रेक बढ़ाया। इसका कारण है चीन में तेजी से फैलता कोरोना। पूरी दुनिया चीन में कोरोना विस्फोट की आशंका जता रही है। कई विशेषज्ञों का दावा है कि चीन में हालात 2019 से भी बदतर हैं। वहीं चीन के अस्पतालों के हालात भी कुछवैसे ही नजर आ रहे हैं जैसे की कोरोना की दूसरी लहर के दौरान भारत में

देखने को मिले थे। मरीजों की संख्या इतनी हो गई है कि उन्हें जमीन पर लिटाना पड़ रहा है।

जा सकती है 20 लाख लोगों की जान
ये तो कुछ भी नहीं है। अममान है कि चीन में कोरोना से 20 लाख लोगों की मौत हो सकती है। इसके अलावा 80 करोड़ लोग संक्रमित हो सकते हैं। पूर्वोत्तर चीन में अस्पृतालों में लाखों का अंबार लग गया है लेकिन सरकार उसे छिपाने में जुट गई है। वहीं स्वास्थ्य अधिकारी की माने तो चीन इस सदी में कोविड संक्रमण की तीन संभावित लहरों में

से पहली लहर का अनुभव कर रहा है।

शवदाहगृह पर बढ़ा दवाब

चीन में एक बार फिर से भयावह हालात है। ये हालात बता रहे हैं कि वहां कोविड एक बार फिर से चरम पर है। चीन में कोविड से बढ़ती मौतों के बाद शवदाह गृहों पर काफी दवाब बढ़ गया है। बीजिंग के 2 प्यूनरल होम्स 24 घंटे ऑपरेट हो रहे हैं। एक दिन में 20-20 शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। प्यूनरल होम के 10 में से सात स्टॉफ कोविड पॉजिटिव होने के बावजूद काम में जुटे हैं।

नोबेल विजेता डेविड बीसले संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम प्रमुख से इस्तीफा देंगे

रोम। नोबेल पुरस्कार जीतने वाले संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम के कार्यकारी निदेशक डेविड बीसले ने कहा कि वह दुनिया के सबसे बड़े मानवीय संगठन का छह साल तक नेतृत्व करने के बाद इस्तीफा देंगे। कार्यक्रम को दो साल पहले शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य बीसले 1995 से 1999 तक साउथ कैरोलाइना के गवर्नर रह चुके हैं। एक बयान में बीसले ने कहा कि वह अप्रैल 2023 में अपना कार्यकाल समाप्त होने पर पद से इस्तीफा दे देंगे। उन्होंने कहा कि इस पद पर काम करना मेरे जीवन का



सबसे बड़ा आनंद और सबसे ज्यादा सिरदर्द वाला काम रहा। सरकारों और लोगों की उदारता के कारण हमने लाखों लोगों को भोजन मुहैया कराया लेकिन वास्तविकता यह है कि हम सभी को भोजन मुहैया नहीं करा पाए और समृद्ध विश्व में भुखमरी की समस्या बनी हुई है। बीसले को 2017 में अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस पद पर नियुक्त किया था। विश्व खाद्य कार्यक्रम ने भूख से लड़ने और ऐसे वक्त में युद्ध तथा संघर्ष के हथियार के रूप में इसके इस्तेमाल को खत्म करने की कवायद के लिए 2020 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था जब कोरोना वायरस संक्रमण ने भुखमरी के हालात और बदतर कर दिए थे।

अमेरिकी खुफिया एजेंसी के प्रमुख ने कहा पीएम मोदी की सलाह का असर राष्ट्रपति पुतिन पर दिख रहा

वाशिंगटन (एजेंसी)। केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) के प्रमुख विलियम बर्न्स ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग द्वारा यूक्रेन में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर करने का रूस पर असर पड़ा है। बर्न्स ने कहा कि उन्हें लगता है कि (रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर) पुतिन और उनके आपसपास के लोगों ने डराने के लिए परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की धमकी दी।

एक साक्षात्कार में सीआईए के निदेशक ने कहा कि अमेरिका ने रूसियों को यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके (परमाणु खतरे के) गंभीर परिणाम हो सकते हैं। उन्होंने कहा मुखे लगता है कि शी और पीएम मोदी का परमाणु हथियारों के इस्तेमाल को लेकर चिंता जाहिर करने का भी काफी फायदा हुआ है। मुखे लगता है कि इसका रूस

पर भी असर पड़ा है।’



इस परीक्षण का मकसद पड़ोसी देशों की गतिविधियों पर नजर बनाए रखना है। इतना ही नहीं किम जोंग इस सैटेलाइट की लॉन्चिंग अप्रैल 2023 तक पूरा करना चाहते हैं। यह रिपोर्ट दक्षिण कोरियाई और जापानी सेनाओं द्वारा अपने पूर्वी तट की ओर दो मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलों की लॉन्चिंग के बाद आई है। ये उत्तर कोरिया के लिए अपनी तरह का

अलग परीक्षण है। उन्होंने उत्तर कोरियाई सेना का हौसला बढ़ाते हुए हर वक्त युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। किम जोंग उन ने सेना के अधिकारियों को एक साथ युद्ध के कई मोर्चों पर प्लान बनाने को कहा। वहीं सफल परीक्षण के बाद आशंका जताई जा रही है कि उत्तर कोरिया का मिसाइल प्रोग्राम और तेज हो सकता है।

प्रचंड ने देउबा से मिलकर नेपाल का प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जताई: रिपोर्ट – दोनों नेताओं ने सत्तारूढ़ गठबंधन को आगे ले जाने के तौर तरीकों और नयी सरकार के गठन पर चर्चा की

लाहौर (एजेंसी)। कांटमांडू (ईएमएस)। सीपीएन-माओइस्ट सेंटर के अध्यक्ष पुष्प कमल दहल प्रचंड ने नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा से मुलाकात की और देश का अगला प्रधानमंत्री बनने की कथित तौर पर इच्छा जताई है। मुलाकात के दौरान दोनों नेताओं ने सत्तारूढ़ गठबंधन को आगे ले जाने के तौर तरीकों और नयी सरकार के गठन पर चर्चा की। हाल ही में हुई बैठक इसलिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी सरकार बनाने के लिए राजनीतिक दलों को अपना दावा पेश करने के लिए बुलाने पर विचार कर रही है। राष्ट्रपति भंडारी के प्रेस विशेषज्ञ टीका ढकाल ने बताया कि राष्ट्रपति ने अभी तक कोई विशेष दिन निर्धारित नहीं किया है। हालांकि वह बहुत जल्द राजनीतिक दलों को दावा पेश करने के लिए बुलाएंगी। किसी पार्टी या गठबंधन को स्पष्ट बहुमत के लिए 275 सदस्यीय हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में 138 सीट की जरूरत है लेकिन किसी भी पार्टी के पास सरकार बनाने के लिए पर्याप्त

संख्या में सीट नहीं है। सत्तारूढ़ गठबंधन के पास सीट सदन में बहुमत के आंकड़े के आसपास है लेकिन अब भी इस बारे में फैसला नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल का नेतृत्व कौन करेगा।

देउबा के नेतृत्व वाली नेपाली कांग्रेस (एनसी) नवंबर में हुए चुनाव में 89 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। सत्तारूढ़ गठबंधन के अन्य सहयोगियों ने मिलकर 47 सीट हासिल की हैं। इनमें सीपीएन-माओइस्ट सेंटर (32) सीपीएन-यूनिफाइड सोशलिस्ट (10) लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी (4) और राष्ट्रीय जनमोर्चा का एक सदस्य है। नवगठित राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी (आरएसपी) ने भी सरकार गठन में नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व वाले पांच दलों के गठबंधन को समर्थन देने की पेशकश की है। 20 नवंबर को हुए चुनाव में आरएसपी 20 सीट के साथ चौथी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। नेपाली कांग्रेस के प्रवक्ता प्रकाश शरण महत ने कहा कि प्रचंड ने प्रधानमंत्री देउबा के

साथ बैठक में पांच वर्षीय कार्यकाल के शुरूआती छह साल के लिए नेपाली कांग्रेस से प्रधानमंत्री बनने के लिए औपचारिक रूप से समर्थन मांगा। नेपाल में 20 नवंबर को हुए चुनाव से पहले गठबंधन बनाते समय देउबा और प्रचंड ने कथित तौर पर बारी-बारी से सरकार का नेतृत्व करने के लिए एक समझौता किया था।

महत ने कहा कि यह अधिक स्वाभाविक होगा कि चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरी नेपाली कांग्रेस सरकार का नेतृत्व करे। खबर के अनुसार यह पूछे जाने पर कि क्या प्रचंड ने नया प्रधानमंत्री बनने के लिए देउबा से समर्थन मांगा है सीपीएन-माओइस्ट सेंटर के नेता नारायण काजी श्रेष्ठ ने कहा कि उन्होंने देउबा से जानना चाहा है कि वह कैसे आगे बढ़ना चाहते हैं। इस पर देउबा ने जवाब दिया कि गठबंधन के सभी सहयोगियों को अपने संबंधित संगठनों के भीतर फैसला करना चाहिए।